एयर इंडिया सीईओ ने पेशाब करने की घटना के लिए माफी मांगी, चालक दल-पायलट को ड्यूटी से हटाया गया

नई दिल्ली ।
एयर इंडिया के यात्री के पेशाब करने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैंपबेल विल्सन ने नवंबर में न्यूयार्क से आ रहे एक विमान में एक यात्री के एक साथी महिला यात्री पर पेशाब करने के लिए शनिवार को माफी मांगी और कहा कि चालक दल के चार सदस्यों और एक पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि है कि एयरलाइन उड़ानों में शराब परोसने की नीति की भी समीक्षा कर रही है।

इसके साथ ही एयर इंडिया के सीईओ-एमडी कैंपबेल विल्सन ने कहा है कि 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच संचालित एआई 102 में हुई घटना के मामले में चार केबिन क्रू और एक पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच लंबित रहने तक ड्यूटी रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने कहा, उड़ान में शराब की सेवा नीति की एयरलाइन समीक्षा करेगी। घटना से निपटने के तरीके को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे विल्सन ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन इस मुद्दे से बेहतर तरीके से निपट सकती थी। भविष्य में उन्होंने अनियंत्रित व्यवहार की एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली बनाने का दावा किया। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, एयर इंडिया उड़ान के दौरान उन घटनाओं को लेकर बहुत चिंतित है जहां हमारे विमान में अपने सह-यात्रियों के निंदनीय कृत्यों के कारण यात्रियों को परेशानी पड़ रही है। हमें खेद है और हम इन अनुभवों से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया स्वीकार करती है कि वह इन मामलों को हवा और जमीन दोनों जगहों पर बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। वे इस मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। एयरलाइन की ओर से उपद्रवी यात्री की सूचना कानून प्रवर्तन अधिकारियों को तत्काल नहीं दिए जाने पर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने कर्मचारियों को सलाह दी कि वे किसी भी समझौते पर पहुंचने के बावजूद सभी घटनाओं की रिपोर्ट करें।

न्यूज ब्रीफ

दिग्गज कारोबारी जैक मा का अब नहीं रहेगा एंट ग्रुप पर नियंत्रण, कंपनी ने की ये बड़ी घोषणा

नई दिल्ली । चीन की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की सहयोगी एंट ग्रुप ने शनिवार को कहा कि उसके संस्थापक जैक मा अब चीन की फिनटेक दिग्गज कंपनी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे। माना जा रहा है कि दो साल पहले शेयर बाजार में कदम रखने के तुरंत बाद शुरू की गई नियामकीय कार्रवाई के कारण यह कदम उठाया जा रहा है। बता दें कि एंट का 37 अरब डॉलर का आईपीओ 2020 में अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था। उसके बाद दिग्गज कंपनी का जबरन पुनर्गठन कर दिया। उसी समय से अटकलें लग रही थीं कि चीनी के अरबपति जैक मा अब अपना नियंत्रण छोड़ देंगे। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि मा के नियंत्रण छोड़ने से कंपनी के लिए अपने आईपीओ को फिर से लाने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, इस बदलाव के परिणामस्वरूप लिस्टिंग नियमों के कारण आईपीओ आने में और देरी होने की संभावना है। चीन के घरेलू शेयर बाजार में कंपनियों को नियंत्रण में बदलाव के बाद लिस्टिंग के लिए तीन साल इंतजार करना पड़ता है। कंपनियों को शंघाई के नैस्डैक शैली के बाजार में लिस्टिंग के लिए दो साल और हांगकांग में एक साल इंतजार करना पड़ता है। 2020 में एक्सचेंजों के साथ दायर एंट के आईपीओ प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, मा के पास ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड की सहयोगी एंट में केवल 10प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन उनका संबंधित संस्थाओं के माध्यम से कंपनी पर है। प्रोस्पेक्टस से पता चला है कि मा निवेश फर्म हांग्जो युनबो का दो अन्य ऐसे संस्थाओं पर नियंत्रण था जिनके पास एंट की संयुक्त 50.5प्रतिशत हिस्सेदारी है।

77प्रतिशत लोग इस साल खरीदना चाहते हैं घरः कीमतें और ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी इसकी वजह

नई दिल्ली। इस साल हर 10 में से 8 लोग मकान खरीदना चाहते हैं। एक सर्वे में शामिल 77प्रतिशत लोगों ने कहा है कि वे इस साल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने इसके तीन मुख्य कारण बताए। पहला समय के साथ रेंट बढ़ता जा रहा है। दूसरा, प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा लोगों की पहुंच में है। और तीसरा, प्रॉपर्टी का मालिक होने से ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। 47प्रतिशत लोगों ने कहा कि ब्याज दरों और प्रॉपर्टी की कीमतों में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है, अगले कुछ सालों में मकानों की कीमतें उनकी खरीद क्षमता से बाहर निकल जाएंगी। बीते पांच साल में मकानों की प्रति वर्ग फुट औसत कीमत बेंगलुरू में 7प्रतिशत, मुंबई में 3.5प्रतिशत, और दिल्ली-एनसीआर में 4प्रतिशत बढ़ी है। रियल एस्टेट मार्केटप्लेस नोब्रोक्र की एक सर्वे रिपोर्ट से ये रुझान सामने आया।

टेस्ला की ई-कारें अमेरिका से चीन में 43प्रतिशत तक सस्तीः कंपनी ने तीसरी बार दामों में की कटौती, नए इंटीरियर के साथ पेश किया गया मॉडल-एस

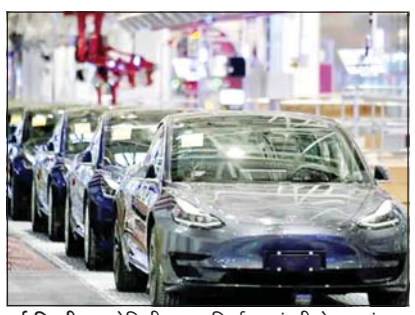

नई दिल्ली । अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला इंक ने चीन में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में तीसरी बार कटौती की है। कंपनी ने शुक्रवार को अपने मॉडल-3 और वाई की कीमतों में करीब दो लाख रुपए तक घटा दिए हैं। इसके साथ ही मॉडल एस सेडान और मॉडल एक्स को भी पेश किया है। चीन में बने मॉडल वाई स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की शुरुआती कीमत करीब 34.84 लाख रुपए से घटाकर 31.32 लाख रुपए (2,59,900 युआन) कर दी है। यह टेस्ला की अमेरिका में तय शुरुआती कीमत 54.53 लाख रुपए की तुलना में 43प्रतिशत कम है। वहीं मॉडल-3 अमेरिका की तुलना में चीन में लगभग 30प्रतिशत सस्ता है। टेस्ला ने कहा कि फिर से डिजाइन किए गए इंटीरियर के साथ पेश किए गए मॉडल-एस की कीमत चीन में 95.24 लाख रुपए (7,89,900 युआन) है। टेस्ला की सबसे तेज ई-कार प्लेड वर्जन की कीमत 1.21 करोड़ रुपए रखी गई है।

बजट तैयार करने में इस 'नवरत्न' की भूमिका सबसे अहम, तय करेंगे देश का आर्थिक भविष्य

नई दिल्ली ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 1 फरबरी, 2023 को 2024 के आम चुनावों से पहले अपना अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेगी। यह बजट घरेलू स्तर पर कई खुशनुमा खबरों के बीच आएगा। भारत जी-20 की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की उम्मीद भी जा रही है। हालांकि इस सबके बीच वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में इस साल पेश होने वाला बजट अहम है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नॉर्थ ब्लॉक में उनके साथ बजट की बरीकियों को अंतिम रूप देने में जुटी टीम के सामने चुनावी साल से पहले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ चलाने का जिम्मा है। ऐसे तो वित्त मंत्री का बजट भाषण ऐसे तो 1 फरबरी 2023 को तय है पर इसे तैयार करने के लिए महीनों पहले से कुछ लोग दिन-रात एक किए हुए हैं।

1. निर्मला सीतारमण - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार वे लगातार पांचवीं बार पेश करेंगी। वित्त मंत्री के रूप में देश का केंद्रीय बजट तैयार करने की प्रक्रिया में उनका सबसे अहम योगदाना होगा। वित्त मंत्री ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है।

2. पीयूष गोयल - देश के वाणिज्य मंत्री के तौर पर पीयूष गोयल का बजट तैयार होने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हाल के दिनों में विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मुकाम तक पहुंचाने में वे बहुत सक्रिय रहे हैं। उनके पास सीमित समय के लिए ही सही पूर्व में वित्त मंत्रालय संभालने का अनुभव भी है। ऐसे में वर्ष 2023-24 का बजट तैयार करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके अनुभव का इस्तेमाल जरूर करेंगी। इस तरह उनकी भूमिका बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान अहम होगी।

3. टीवी सोमनाथन - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद बजट तैयार करने वालों में दूसरा प्रमुख चेहरा वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का होगा। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। उनके नेतृत्व में देश के पूंजी खर्च रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है।

4. अजय सेठ - बजट तैयार करने वालों में एक अहम नाम वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग के प्रभारी सचिव अजय सेठ का है। बजट डिविजन का जिम्मा वही देखते हैं। बजट से जुड़े इनपुट्स और अलग-अलग तरह के वित्तीय विवरण तैयार करने में उनका अहम योगदान होता है।

5. तुहीन कांत पांडेय - तुहीन कांत पांडेय वित्त मंत्रालय के तहत आअने वाले विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। हाल के दिनों ने सरकार ने विनिवेश के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है उनमें तुहीन का बहुत अहम योगदान रहा है। एलआईसी का आईपीओ लाने और एयर इंडिया के निजीकरण में भी उनकी अहम भूमिका रही है।

6. संजय मल्होत्रा - हाल ही में नियुक्त हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आइएएस अधिकारी हैं। उनके ऊपर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि बजट में की गई घोषणाएं सरकार की पॉलिसी और महत्वकांक्षाओं के अनुरूप हों। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि बजट में की गई घोषणाएं धरातल से बहुत दूर ना हों।

7. विवेक जोशी - 2022 के अक्तूबर महीने की 19 तारीख को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव चुने गए विवेक जोशी पर भी बजट तैयार करने की प्रक्रिया में अहम योगदान होगा। इस भूमिका में आने से पहले जोशी गृह विभाग के तहत जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल और निदेशक थे।

8. वी अनंत नागेश्वरन - वी अनंत नागेश्वरन को वर्ष 2022 के बजट के पहले चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर चुना गया था। इस बार जब बजट तैयार किया जा रहा है उस पूरी प्रक्रिया में नागेश्वरन भी अहम भूमिका में हैं। उनके ऊपर वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वे का ड्राफ्ट करने की भी जिम्मेदारी है।

9. शक्तिकांत दास - वर्ष 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाल रहे हैं। देश में महंगाई को काबू करने के लिए कोशिशें करना हो या सरकार की आर्थिक नीतियों का बचाव करना उन्होंने हमेशा अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। ऐसे में आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी इसे नकारा नहीं जा सकता है।

भारत की नजर निष्पक्ष व न्यायपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों पर, पीयूष गोयल बोले- बातचीत सही दिशा में जारी

नई दिल्ली ।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि कई देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने के लिए बातचीत सही दिशा में चल रही है। कुछ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बहुपक्षीय समझौतों पर भी भारत की नजर है।

भारत ने वर्ष 2022 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को लागू कर इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार व वेश को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए पर बातचीत हो रही है। गोयल ने 27वें व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि कई देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता संपन्न करने के लिए बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा, इसके अलावा भारत की नजर एक या दो बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर भी है। हमें उम्मीद है कि इनसे हमें लाभ हो सकता है।

किसी मुक्त व्यापार समझौते के तहत दोनों पक्ष एक-दूसरे के अधिकांश उत्पादों और सेवाओं को शुल्क-मुक्त या न्यूनतम शुल्क पर पहुंच देते हैं। इससे उनके बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है।

गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों का हिस्सा बनना भारत के हित में है। उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि समझौते संतुलित हों और वे दोनों ही देशों के हित में हों। वे दोनों देशों के संवेदनशील पहलुओं का ध्यान रखते हैं और कुछ खास क्षेत्रों को संरक्षण देने में भी मदद करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत हरेक उत्पाद को सक्षम ढंग से नहीं बना सकता है और ऐसी स्थिति में उन उत्पादों का आयात करना महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं कपड़ा, चमड़ा, फुटवेयर और दवा जैसे कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनमें भारत प्रतिस्पर्द्धी है और इनके निर्यात में व्यापार समझौते कारगर साबित हो सकते हैं।

उन्होंने भारत के क्षेत्रीय व्याप आर्थिक भागीदारी (आर-सेप) समझौते का हिस्सा नहीं बनने का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक निष्पक्ष समझौता नहीं है और पूरी तरह असंतुलित है। उन्होंने कहा कि आर-सेप में शामिल एक देश की व्यापार प्रणाली काफी धुंधली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों व सेवाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

अब घर बैठे करा सकेंगे केवाईसी, आरबीआई ने कहा, वीडियो कॉलिंग के जरिए खाताधारकों को मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली ।
बैंक के ग्राहक अब घर बैठे केवाईसी यानी कागजातों को अपने खाते में अपडेट कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि किसी भी बदलाव पर ग्राहक स्व-घोषणा बैंक को दे सकते हैं। बैंकों को कहा गया है कि वे इस घोषणा को ही मंजूर करें। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे व्यक्तिगत ग्राहकों को इस तरह की सुविधा बैंक शाखा में जाए बिना, विभिन्न नॉन फेस-टू-फेस चैनल्स जैसे ईमेल-आईडी, मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (ऑनलाइन बैंकिंग/ इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल एप) या पत्र आदि के माध्यम से प्रदान करें। अगर केवल पते में बदलाव होता है तो ग्राहक उपरोक्त किसी भी चैनल के जरिए संशोधित पता दे सकते हैं। बैंक दो माह में पते का सत्यापन करेगा। आरबीआई ने कहा, बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे समय-समय पर समीक्षा करके रिकॉर्ड को सही रखें, इसलिए ग्राहकों को कुछ मामलों में नई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ सकता है। इन मामलों में बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध व आधिकारिक रूप से वैध केवाईसी दस्तावेज की वर्तमान सूची के अनुरूप नहीं होना या फिर पहले जमा किए गए केवाईसी की वैधता अवधि समाप्त होना शामिल है। केवाईसी कागजात में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या होने का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड आदि शामिल हैं।

नई केवाईसी प्रक्रिया को बैंक शाखा में जाकर, या वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के माध्यम से कहीं से भी पूरा किया जा सकता है। वी-सीआईपी की सुविधा केवल उन्हीं बैंकों में उपलब्ध हो सकेगी, जिन्होंने इसे इनेबल किया हुआ है।

भारत से छिन सकता है सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाले देश का दर्जा, सात प्रतिशत रह सकती है विकास दर

नई दिल्ली ।
मांग में नरमी के साथ विनिर्माण व खनन क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 1.7 फीसदी घटकर 7 फीसदी रह सकती है। ऐसा होने पर भारत सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाले देश का दर्जा खो सकता है।सऊदी अरब इससे आगे निकल सकता है, जिसकी वृद्धि दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में यह संभावना जताई गई है। हालांकि, यह आरबीआई के 6.8प्रतिशत के अनुमान से ज्यादा है। 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर 8.7प्रतिशत रही थी। एनएसओ के मुताबिक, नॉमिनल जीडीपी (बाजार या मौजूदा कीमत पर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य) भी 2022-23 के दौरान 4.1 फीसदी घटकर 15.4 फीसदी रह सकती है। 2021-22 में यह आंकड़ा 19.5 फीसदी रहा था। आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन घटकर 1.6 फीसदी रहने का अनुमान है। 2021-22 में इसमें 9.9 फीसदी की वृद्धि हुई थी। इसी तरह, खनन क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि दर कम होकर 2.4 फीसदी रह सकती है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11.5 फीसदी रही थी। 36.43 लाख करोड़ रुपये बढ़ सकता है अर्थव्यवस्था का आकार चालू वित्त वर्ष में नॉमिनल जीडीपी 36.43 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 273.08 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकती है। 2021-22 में यह आंकड़ा 236.65 लाख करोड़ रहा था। वास्तविक जीडीपी या स्थिर मूल्य (2011-12) पर आकार 2022-23 में 157.60 लाख करोड़ रह सकता है। पहले 147.36 लाख करोड़ का अनुमान था। उत्पादन के मोर्चे पर मिला-जुला प्रदर्शन कृषि क्षेत्र में उत्पादन की दर 3 फीसदी से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 3.5 फीसदी के स्तर पर पहुंच जाएगी। यातायात, होटल और संचार आदि क्षेत्र की वृद्धि दर 11.1 फीसदी से बढ़कर 13.7प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है।

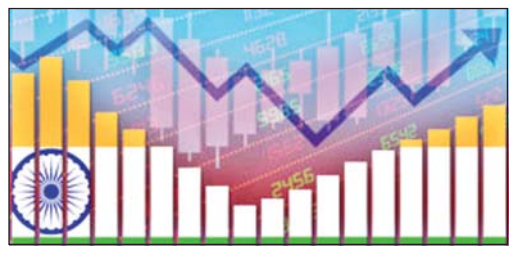

छंटनी की घोषणा के बाद अमेजन संस्थापक जेफ बेजोस के स्टॉक में भारी गिरावट, हुआ 5 हजार करोड़ का घाटा

नई दिल्ली ।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन में हजारों कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा के बाद कंपनी ने संस्थापक जेफ बेजोस के स्टॉक में भारी गिरावट आ गई है। एक दिन में ही कंपनी के शेयर में करीब 1 फीसदी की गिरावट देखने मिलती है। यानी कंपनी के संस्थापक को एक दिन में ही नेट वर्थ में 600 मिलियन डॉलर यानी 5,539 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

बता दें कि ई-कॉमर्स दिग्गज ने बुधवार को कहा था कि अनिश्चित अर्थव्यवस्था के बीच हो रही छंटनी से उसके 18,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे।

अमेजन स्टॉक की कीमतों में गिरावट ने संस्थापक बेजोस के नेट वर्थ को भी प्रभावित किया है, जो एक दिन में 600 मिलियन डॉलर यानी 5,539 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, बुधवार की समाप्ति तक बेजोस की संपत्ति में 675 मिलियन डॉलर की गिरावट रही।

अरबपति जेफ बेजोस की वर्तमान में 108 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और वह दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बता दें कि पिछले साल सितंबर में भारतीय उद्योगपति और देश के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अमेजन के बेजोस को पीछे छोड़ दिया था। गौरतलब है कि बेजोस हाल के महीनों में अमीरों की सूची में कई पायदान नीचे खिसके हैं।

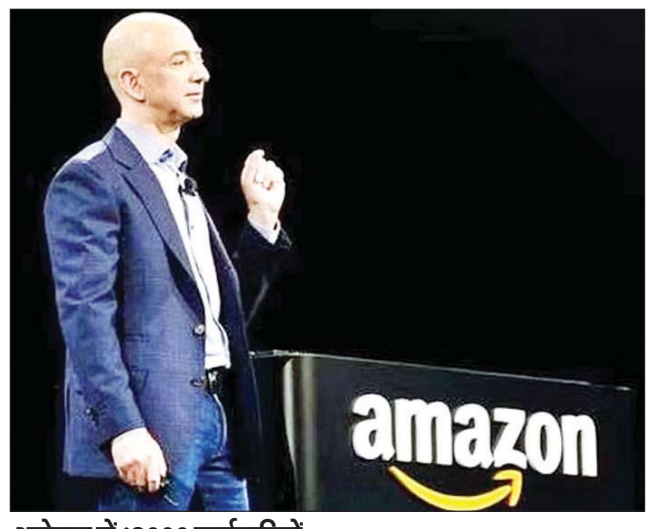

अमेजन में 18000 कर्मचारियों की छंटनी

आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन ने गुरुवार को कहा कि वह 18,000 से अधिक नौकरियों को घटना चाहती है। कंपनी यह कदम लागत में कटौती करने के लिए उठा रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेसी ने कर्मचारियों को भेजे एक नोट में कहा था कि प्रभावित कर्मियों को 18 जनवरी से इसकी सूचना दी जाएगी।

बता दें कि यह कटौती फर्म के लगभग 300,000 मजबूत कॉरपोरेट कार्यबल का लगभग 6प्रतिशत है। यह आंकड़ा नवंबर, 2022 में की गई 10,000 छंटनी से 80 फीसदी ज्यादा है। मौजूदा मंदी के दौर में अमेजन का 18,000 कर्मचारियों को हटाना अब तक की सबसे बड़ी छंटनी होगी। सितंबर अंत तक अमेजन के साथ 15 लाख से अधिक कर्मचारी जुड़े थे।

छंटनी से भारत में लगभग 1,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे

अमेजन के दुनियाभर में 18,000 कर्मियों की छंटनी के फैसले से भारत के करीब 1,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। कंपनी से जुड़े सूत्रों से शुक्रवार को यह जानकारी दी। कंपनी अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में 18,000 से अधिक पदों को समाप्त कर रही है।

सूत्र ने कहा, कंपनी के वैश्विक स्तर पर 18,000 नौकरियों को खत्म करने के निर्णय से देश के लगभग 1,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। एक अन्य सूत्र ने कहा कि अमेजन के भारत में एक लाख कर्मचारी हैं। इस फैसले से यहां एक प्रतिशत कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।

हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन अमेजन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एंडी जेस्सी के एक लेख लिंक साझा किया है। लेख में उन्होंने वैश्विक स्तर पर 18,000 पदों को खत्म करने के कंपनी के फैसले की जानकारी दी है।

जेस्सी ने लिखा है, हम करीब 18,000 पदों को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। इस फैसले से कई समूह प्रभावित होंगे। हालांकि, ज्यादातर पद अमेजन स्टोर और पीएक्सटी (पीपुल, एक्सपीरिएंस और प्रौद्योगिकी) संगठन से संबंधित हैं।'' अमेजन में 31 दिसंबर, 2021 तक लगभग 16,08,000 पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे थे।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017